दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शनिवार 09 नवम्बर 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 42

महत्वपूर्ण एवं खास

तीस हजारी मामला : उत्तर प्रदेश के भी वकील हड़ताल पर

लखनऊ (आरएनएस)। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में पिछले शनिवार को पुलिस और वकीलों के बीच हुई भिड़त के विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश के वकील आज हड़ताल पर हैं। राज्य के सभी जिला और उच्च न्यायालय में काम बंद है। करीब ढाई लाख से ज्यादा वकील हड़ताल पर हैं। बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश के आवाह्न पर हड़ताल हुई है । वकील अपने समय से अदालत में आये ले कन काम बंद रखा। राज्य के किसी भी अदालत में कोई काम नहीं हुआ। राज्य के कई हिस्सों ने वकीलों ने मार्च निकाला और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट परिसर मे हुई हिंसक घटना मे घायल वकीलो को दस दस लाख रूपया का मुआवजा देने की मांग को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा और वकीलो की सुरक्षा के लिये सरकार से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाने की मांग की।

त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जस्टिस कुरैशी के नाम को केंद्र की मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस अकील कुरैशी को त्रिपुरा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। जस्टिस कुरैशी के प्रमोशन और नियुक्ति का मामला लंबे समय से केंद्र सरकार के समक्ष लंबित था। सूत्रों के मुताबिक बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। अब राष्ट्रपति जस्टिस कुरैशी की नियुक्ति वारंट पर हस्ताक्षर करेंगे। दरअसल कॉलेजियम ने पहले जस्टिस कुरैशी का नाम मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए भेजा था। सरकार के समक्ष लंबे समय तक यह फाइल अटकी रही। बाद में केंद्र की सलाह को देखते हुए कॉलेजियम ने प्रस्ताव में बदलाव कर जस्टिस कुरैशी का नाम त्रिपुरा हाईकोर्ट के लिए भेजा था। वहीं बृहस्पतिवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 13 नवंबर तय करते हुए कहा, तब तक जस्टिस कुरैशी बॉम्बे हाईकोर्ट में ही तैनात रहेंगे।

पाक जाने को लेकर सिद्धू को मिली अनुमति

» तीन बार सरकार को लिखा था पत्र

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को सरकार ने करतारपुर साहिब गलियारे के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने और गुरुद्वारे के दर्शन की सशर्त अनुमति दे दी। कांग्रेस के नेता, विधायक एवं पूर्व मंत्री सिद्धू को नौ नवंबर को करतारपुर साहिब जाने की राजनीतिक मंजूरी मिल गयी है लेकिन यह मंजूरी सशर्त है। वह उद्घाटन अवसर पर जाने वाले पहले जत्थे में शामिल होंगे जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जाएंगे। क्रिकेट जगत से राजनीति में कदम रखने वाले सिद्धू ने विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर को आज दिन में भेजे अपने तीसरे पत्र में लिखा था कि कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में वह केन्द्र सरकार की अनुमति मिलने पर ही पाकिस्तान जाने के इच्छुक हैं।

एलईडी बैन मामले में 6 फर्म के खिलाफ प्राथमिकी

लखनऊ (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचना विभाग में एलईडी वैन के पंजीयन प्रमाण पत्र में हेरा फेरी व टेम्परिंग के मामले में छह फर्म के खिलाफ शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कराई है। सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी के निर्देश पर 6 फर्मों के विरुद्ध हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इन फर्म को काली सूची में भी डाला गया है। टेण्डर में फर्जी दस्तावेज दिये जाने के मामले में भी जांच के आदेश दिये गये हैं। प्रवक्ता ने कहा कि श्रीमंत ऋक्सा पब्लिसिटी, श्रीमंत फिस्कान मीडिया, श्रीमंत खेन्सा एडवरटाइजिंग, श्रीमंत एडमायर पब्लिसिटी, श्रीमंत मीडिया लाजिक्स और श्रीमंत मातेश्वरी इण्टरप्राइजेज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

सोनिया, राहुल व प्रियंका की वापस होगी एसपीजी सुरक्षा

» केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की एसपीजी (स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स) सुरक्षा हटाने का फैसला लिया है। इन तीनों की एसपीजी सुरक्षा को चरणों में हटाया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद पूरे गांधी परिवार को एसपीजी सुरक्षा कवर देने का फैसला किया गया था।

सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय की सुरक्षा समीक्षा कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कमेटी की सिफारिश के अनुसार अब गांधी परिवार के सदस्य को एसपीजी के बजाय सीआरपीएफ की जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की जाएगी। गृह मंत्रालय की बैठक में गांधी परिवार की सुरक्षा की समीक्षा की गई और पाया गया कि उन्हें बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। इस वजह से उनके सुरक्षा इंतजामों को बदलने का फैसला किया गया। किसी भी व्यक्ति के सामने संभावित खतरे को देखते हुए यह सुरक्षा दी जाती है। सूत्रों के अनुसार उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया कि फिलहाल गांधी परिवार को कोई खतरा नहीं है और ऐसे में जेड प्लस की सुरक्षा पर्याप्त होगी। सूत्रों के अनुसार बैठक में एसपीजी अधिकारियों की कई रिपोर्ट को पेश किया गया। इन रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि गांधी परिवार से कई बार कहने के बावजूद वे विदेश दौरों पर अपने साथ एसपीजी सुरक्षा नहीं ले गए। इसका मतलब कि उन्हें एसपीजी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय समय-समय पर सुरक्षा कवर को लेकर समीक्षा करता रहता है। सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि यह निर्णय राजनीतिक बदले की भावना से लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सुरक्षा से भी एसपीजी कवर हटाकर सीआरपीएफ की जेडप्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। वहीं कांग्रेस के अहमद पटेल ने कहा कि इससे देश के उन 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवारों की सुरक्षा के साथ समझौता हुआ है, जिन्होंने आतंक और हिंसा के खिलाफ कार्रवाई की थी। अहमद पटेल ने कहा कि गांधी परिवार की जिंदगी के साथ खिलावड़ करके भाजपा निजी बदले के चरम पर उतर चुकी है।

एसपीजी सुरक्षा अब सिर्फ प्रधानमंत्री के पास

गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाने के फैसले के बाद अब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ही एसपीजी सुरक्षा रहेगी। वर्तमान में भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गांधी परिवार को ही एसपीजी की सुरक्षा प्राप्त थी।

एसपीजी सुरक्षा और जेड प्लस सुरक्षा में क्या है अंतर

ह सुरक्षा का सबसे ऊंचा स्तर है। इस सुरक्षा में तैनात कमांडों के पास आधुनिक हथियार व उपकरण होते हैं। एसपीजी के बाद जेड प्लस भारत की सर्वोच्च सुरक्षा श्रेणी है। व्यक्ति की सुरक्षा में 36 जवान लगे होते हैं। इसमें 10 से ज्यादा एनएसजी कमांडो के साथ दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के कमांडो और राज्य के पुलिसकर्मी शामिल होते हैं।

नोटबंदी पर कांग्रेस ने फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना

नई दिल्ली (आरएनएस)। नोटबंदी के तीन साल पूरे होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर शुक्रवार को हमला बोला। उन्होंने नोटबंदी को आतंकी हमला करार देते हुए कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए। आठ नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए 500 और 1000 रुपये के नोटों के प्रचलन से बाहर किए जाने की घोषणा की थी।

राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि नोटबंदी आतंकी हमले को तीन साल गुजर गए हैं जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, कई लोगों की जान ले ली, कई छोटे कारोबार खत्म कर दिए और लाखों भारतीयों को बेरोजगार कर दिया। उन्होंने हैशटैग 'डिमोनेटाइजेशन डिजास्टर' का प्रयोग करते हुए कहा कि इस निंदनीय हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को कानून के समक्ष लाया जाना बाकी है। कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और उन्हें आज का तुगलक कहा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1330 में देश की मुद्रा को अमान्य करार दिया था। आज के तुगलक ने भी आठ नवंबर, 2016 को यही किया था। उन्होंने कहा कि तीन साल गुजर गए और देश भुगत रहा है क्योंकि अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी है, रोजगार छिन गया है।

भारत ने लेखक आतिश तासीर का रद्द किया ओसीआई कार्ड

» पीएम मोदी को बताया था डिवाइडर इन चीफ

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत ने लेखक और पत्रकार आतिश अली तासीर का ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड रद्द कर दिया है। ब्रिटेन में जन्मे पाकिस्तानी मूल के लेखक आतिश अली तासीर ने लोकसभा चुनाव से पहले टाइम मैगजीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्डिवाइडर इन चीफश् कहा था। बताया जा रहा है कि उन्होंने कथित तौर पर यह तथ्य छुपाया कि उनके पिता पाकिस्तानी मूल के थे। बता दें कि आतिश तासीर के पिता सलमान तासीर पाकिस्तान के पंजाब सूबे के गवर्नर थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार, तासीर ओसीआई कार्ड के लिए अयोग्य हो गए हैं क्योंकि ओसीआई कार्ड किसी ऐसे व्यक्ति को जारी नहीं किया जाता है जिसके माता-पिता या दादा-दादी पाकिस्तानी हों। गृह मंत्रालय ने बताया कि 38 साल के तासीर ने स्पष्ट रूप से बहुत बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं किया और जानकारी को छुपाया है। कानून के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति ने धोखे से फर्जीवाड़ा कर या तथ्य छुपा कर ओसीआई कार्ड हासिल किया है तो कार्ड धारक का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा और उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा।

बाघ के गांव में घुसने से ग्रामीणों में दहशत

रायसेन (आरएनएस)। मध्यप्रदेश के रायसेन जिले के बाड़ी कस्बे से मात्र एक किलोमीटर दूर ग्राम सिरवारा में आज अचानक बाघ के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और लोग अपने घरों को छोड़कर छत पर चढ़ गए हैं। वनमंडलाधिकारी अनिल सिंह भी गांव में बाघ के आने खबर मिलते ही मौके पर पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि वन विभाग और पुलिस की टीम बाघ को पकड़ने के प्रयास में है। भोपाल वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने के लिए रवाना हुई है।

मुख्यमंत्री पद से फडणवीस ने दिया इस्तीफा, राज्यपाल ने किया मंजूर

मुंबई (आरएनएस)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को इस्तीफा सौंप दिया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव परिणाम 24 अक्टूबर को आए थे। परिणाम आए एक पखवाड़े का समय बीत जाने के बावजूद गठबंधन करके चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर सहमति नहीं बन पाई।राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद फडणवीस ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, मैंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया और मेरा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को सबसे 105 सीटें मिलीं जबकि उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ी शिवसेना ने 56 सीटें जीती हैं। शिवसेना मुख्यमंत्री पद 50-50 के फार्मूले पर चाहती थी जिस पर भाजपा सहमत नहीं हुई। फडणवीस ने कहा कि शिवसेना और भाजपा के बीच ढाई-ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद को लेकर उनके सामने कभी कोई निर्णय नहीं हुआ। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी इस बारे में जानकारी चाही तो दोनों ने भी ऐसे किसी फार्मूले के फैसले से इन्कार किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा नतीजों के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में विकल्प खुले होने की बात कहीं थी, इसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए

एक सप्ताह बाद अयोध्या में शुरू हो जाएगा पत्थर तराशी का काम

अयोध्या (आरएनएस)। अयोध्या में भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले राममंदिर के लिए पत्थर तराशने के रूके काम पर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने सफाई दी है। विहिप का कहना है कि पत्थर तराशी का काम अनवरत चलने वाला है। तराशी का काम कुछ निजी कारणों से रूका था। एक सप्ताह में काम पुनः शुरू हो जाएगा। विश्व हिन्दू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि पत्थर तराशी का काम बंद होने की अफवाह फैलाई गई है। जब कारसेवकों पर गोली चली तब अयोध्या में पत्थर तराशी का काम नहीं रूका तो अब क्या रूकेगा।

उन्होंने बताया कि सितंबर 1990 से कार्यशाला में लगातार पत्थर तराशी का काम हो रहा है। पहले 150 कारीगर काम कर रहे थे। 1992 में विवादित ढांचा ध्वस्त होंने के बाद भी कार्यशाला में काम नहीं रूका था। तो अब क्या रूकेगा। यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। तराशी का काम करने वाले कारीगरों के निजी कारणों से काम रूका हुआ है। लेकिन एक सप्ताह में पुनः शुरू हो जाएगा।

शरद शर्मा ने बताया कि कार्यशाला में काम रोकने के लिए सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं था। यह निजी कारणों से रोका गया था। इसमें कोई अदालती कार्यवाही का लेना देना नहीं है। अब सप्ताह भर बाद पुनः शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पत्थर तराशी का काम करने वाले गुजरात व अन्य प्रदेशों के हैं। वह अपने निजी कायरें से वहां गए हैं तभी काम रूक गया है। दो महीने पहले मूर्तिकार की मौत हो गई। तब भी काम रुका हुआ था। इसके बाद दीपावली का पर्व आ गया। सभी लोग छुट्टी पर चले गए।

सिवनी में ट्रैक्टर ट्राली पलटने से तीन बच्चों की मौत

सिवनी (आरएनएस)। मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के कामता गांव के समीप आज एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलट जाने से उसमें सवार तीन बच्चों की मौत हो गयी।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सिवनी-मंडला सड़क मार्ग स्थित कामता गांव से सुबह ट्रैक्टर ट्रॉली खेत से मक्का लाने के लिए निकली। इसी बीच रास्ते में पलट गयी। दुर्घटना में तीन बच्चे संदीप (08), युवराज (06) और अनुज चंद्रवंशी की घटना स्थल पर ही मौत हो गयी। तीनों बच्चे ग्राम पंचायत कामता के उप सरपंच दशरथ चंद्रवंशी के परिवार के हैं।

मायावती का बड़ा फैसला, मुलायम के खिलाफ वापस लिया मुकदमा

» गेस्ट हाउस कांड

लखनऊ (आरएनएस)। लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी से सभी रिश्ते तोड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के खिलाफ 1995 के गेस्ट हाउस केस को वापस ले लिया है।मायावती के इस कदम को उत्तर प्रदेश में पिछले महीने 11 विधानसभा सीटों पर हुये उपचुनाव में बसपा की खराब हालत के बाद उनके फिर से सपा के नजदीक जाने के रूप में देख जा रहा है। बसपा के महासचिव सतीश चन्द्र मिश्र ने कहा कि लोकसभा चुनाव के वक्त जब दोनों दलों में समझौता हुआ था तब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गेस्ट हाउस केस से मुलायम सिंह यादव का नाम वापस लेने की अपील की थी। बसपा प्रमुख ने वायदा किया था कि वो केस को वापस ले लेंगी और उन्होंने अपना वायदा निभाया है।

दो महीने से घर में मां और बहन के शव के साथ रह रही थी महिला

अयोध्या (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, यहां एक महिला अपनी मां और बहन के शवों के साथ दो महीने से अधिक समय से रहती मिली। देवकली पुलिस थाना क्षेत्र की आदर्श नगर कॉलोनी में पड़ोसियों द्वारा एक घर से तेज बदबू आने की शिकायत किए जाने पर गुरुवार को पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने दरवाजा खोलने पर दीपा को अपनी मां पुष्पा श्रीवास्तव और बहन विभा के मृत शरीर के साथ सोता पाया। सर्किल अधिकारी अरविंद चौरसिया ने संवाददाताओं को बताया कि दीपा के पिता व पूर्व सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट विजेंद्र श्रीवास्तव की 1990 में मौत हो गई थी। वह अपनी मां और तीन बहनों के साथ घर में रहती थी, जिनमें से एक रूपाली की कुछ साल बाद मौत हो गई।

इसके बाद पुष्पा श्रीवास्तव और उनकी बाकी दो बेटियां, विभा और दीपा मानसिक रूप से बीमार हो गईं। उन्होंने पड़ोसियों के साथ बातचीत करना बंद कर दिया था। पुष्पा और विभा की मौत लगभग दो महीने पहले हुई थी और दीपा उनके शवों के साथ रह रही थी।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि शव इस हद तक सड़ चुके थे कि हड्डियां दिखाई दे रही थीं, जिसका मतलब है कि दोनों की मौत करीब दो महीने पहले हुई होगी। मौत के कारण का पता लगाने के लिए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और दीपा को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है और फिर उसकी स्थिति के आधार पर या तो पागलखाने या फिर आश्रय गृह भेज दिया जाएगा।

अयोध्या और देश के आर्थिक हालात पर संघ-भाजपा नेताओं का मंथन

नई दिल्ली (आरएनएस)। अयोध्या के राममंदिर-बाबरी मस्जिद के फैसले से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के बीच समन्वय बैठक हुई है। इस दौरान अयोध्या से जुड़े मामले के साथ-साथ देश के आर्थिक हालात पर संघ और बीजेपी नेताओं ने मंथन किया।

अयोध्या के राममंदिर-बाबरी मस्जिद की जमीन के मालिकाना हक के फैसले से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के बीच इस समन्वय बैठक में अयोध्या और देश की आर्थिक स्थिति के मुद्दे पर चार घंटे तक मंथन चला। संघ के आर्थिक मामलों से जुड़े हुए अनुषांगिक संगठनों ने श्रम कानून बदलाव से उपजी चिंताएं, ई-कॉमर्स और मुक्त व्यापार समझौते पर अपने रुख से वित्त मंत्री को अवगत कराया। भाजपा और संघ के बीच सेतु का काम कर रहे कृष्णगोपाल, अरुण कुमार, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और केंद्र सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह, संतोष गंगवार समेत कई नेता समन्वय बैठक में शामिल हुए।

बेवजह बयान देने से बचने की सलाह

सूत्रों की मानें तो अयोध्या पर आने वाले फैसले के बाद समाज में समरसता और शांति बनाए रखना पर चर्चा हुई। हालांकि बीजेपी और संघ के नेता पिछले कई दिनों से लगातार अल्पसंख्यक नेताओं और धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर समाज में शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को बेवजह बयान न देने की हिदायत दी है। इसके अलावा अपने सभी सांसदों को अपने-अपने क्षेत्र में रहने को भी कहा गया है। इस दौरान आर्थिक मामलों से जुड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छह अनुषांगिक संगठन ने भाग लिया। इसमें भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, लघु उद्योग भारती, सहकार भारती और ग्राहक पंचायत शामिल थे। संघ के अनुषांगिक संगठनों ने सूक्ष्म व लघु उद्योग का मापदंड बदलने, श्रम कानून बदलाव से उपजी चिंताएं, ई-कॉमर्स व मुक्त व्यापार समझौते, समेत अन्य मामलों पर अपने रुख को वित्तमंत्री के सामने रखा।